प्रसार भारती
आकाशवाणी केन्द्र शिमला
23.05.2025/प्रादेशिक समाचार/1800बजे

सीबीआई जांच

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने बहुचर्चित विमल नेगी मौत मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी है। हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल ने आज इस संबंध में फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह, डीजीपी और शिमला पुलिस की एस.आई.टी. की जांच रिपोर्ट को आधार बनाते हुए मामला जांच के लिए सीबीआई को सौंपने का फैसला सुनाया। इस मामले में याचिकाकर्ता मृतक विमल नेगी की धर्म पत्नी किरण नेगी के अधिवक्ता आर के बावा ने बताया कि अदालत ने आदेश दिया कि सीबीआई जांच टीम में हिमाचल कैडर का कोई भी अधिकारी शामिल नहीं होगा। अदालत ने मामले में शिमला ज़िला पुलिस को भी फटकार लगाई है और कहा है कि वह दो महीने बीत जाने के बाद भी किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है।

विमल नेगी की वाइफ ने यहां एक पेटिशन कर रही थी जिसमें उन्होंने कहा कि उनकी जो हस्बैंड की डेथ हुई है in mysterious circumstances उसके उपर जो है फेयर इन्वेस्टीगेशन नहीं हुई है तो वो जो पेटिशन है वो कोर्ट ने आज allow करी है और मै जो इन्वेस्टीगेशनहै वो मै सी बी आई को ट्रान्सफर कर दी है इसमें indipendent enquire करेंगे और हिमाचल कोई भी ऑफिसर जो है उसमें अपने एस आई टी में अगर करते हैं तो उसमें associate नहीं करेगा ।

इस मामले में मृतक चीफ इंजीनियर विमल नेगी की पत्नी किरण नेगी ने पुलिस जांच पर सवाल उठाए थे और अदालत से निष्पक्ष जांच के लिए मामले को सीबीआई को सौंपने की गुहार लगाई थी।

सीबीआई जांच–2

विमल नेगी के परिजनों ने फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि हाईकोर्ट के फैसले से सच्चाई की जीत हुई है और अब सीबीआई मामले की निष्पक्ष जांच कर सकेगी, जिससे परिवार को न्याय मिलेगा।

आज हमें जो माननीय न्यायालय ने हमारे जो जो आप फैसला दिया है, इससे हम जो हैं बहुत ही प्रसन्न हैं और आगे भी हम आशा करते हैं कि जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जहां भी है केस आगे दिया गया है केंद्रीय एजेंसी को उसमे जो हमें पूरा पूरा विश्वास है कि हमें न्याय मिलेगा ।आप जो है पहले दिन से देखिए बचाने की कोशिश की जा रही है। हमारी सुनवाई नहीं हो रही थी। आप देखे पेनड्राइव जो हैकहाँ से मिला इनको और मोबाइल जो है वो बोलते State Forensic Lab में है अब जब हमारी पिछली पेशी हुई थी हाई कोर्ट में तो हमे तब पता लगा की मोबाइल भी मिला है ये पहले दिन से ही हमे कोई भी इनकी तरफ से सपोर्ट नहीं मिली है सरकार की तरफ से और सरकार मिली हुई है इनको बचा रही है ।

इस बीच नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने विमल नेगी मौत मामले की जांच सीबीआई को सौंपने के प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। जयराम ठाकुर ने कहा कि अब इस मामले की निष्पक्ष जांच हो

सकेगी और विमल नेगी व उनके परिवार को न्याय मिलेगा। उन्होंने कहा कि भाजपा विमल नेगी के परिवार के साथ खड़ी है।

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा कि हाईकोर्ट द्वारा विमल नेगी मौत मामले की जांच सीबीआई को सौंपने से सत्य की जीत हुई है। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के फैसले से इस मौत के लिए जिम्मेदार वास्तविक लोगों को सजा मिल सकेगी। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट का ये फैसला प्रदेश सरकार की नीयत पर भी आक्षेप है।

उच्च न्यायालय ने सीबीआई इंक्वायरी के लिए आदेश पारित किए, यहजहां सत्य की जीत है, वहीं हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार, माननीय मुख्यमंत्री, होममिनिस्टर, उनके ऊपर सीधा–सीधा एक आक्षेप है, क्यों उन्होंने इतने दिन तकसीबीआई की जांच को ठुकराया, क्यों उन्होंने इतने गंभीर मसले को और गंभीरतानहीं दिखाई और इतने दिन तक साक्षियों को मिटाने का काम किया गया।

सीबीआई जांच–3

विधायक व पूर्व मंत्री बिक्रम ठाकुर और भाजपा मीडिया प्रभारी कर्ण नंदा ने हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि इस फैसले से साबित हो गया है कि प्रदेश सरकार पर विमल नेगी मामले पर जो भी आरोप लगे थे, वह सही थे। उन्होंने कहा कि वास्तव में प्रदेश सरकार विमल नेगी के परिजनों का दर्द ही नहीं समझ पाई। उन्होंने कहा कि इस फैसले जहां सच्चाई की जीत हुई वहीं कांग्रेस सरकार की पोल भी खुल गई है।

मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भेंट की। मुख्यमंत्री ने राज्य से संबंधित विभिन्न बजटीय और वित्तीय मामलों से केंद्रीय मंत्री को अवगत करवाया। मुख्यमंत्री ने तुर्की से आयातित सेब का मामला भी उठाया। उन्होंने हिमाचल प्रदेश सहित देश के सेब उत्पादकों के हितों की रक्षा के लिए सेब पर आयात शुल्क में एक सर्वव्यापी वृद्धि के लिए भी आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने वित्त मंत्री से हिमाचल और अन्य विशेष श्रेणी राज्यों की उधार सीमा को कम से कम दो प्रतिशत बढ़ाने का अनुरोध किया। उन्होंने राज्य में राजकोषीय प्रबंधन में सुधार के लिए राज्य सरकार द्वारा की गई विभिन्न पहलों और कई वित्तीय बाधाओं के बावजूद वित्तीय संसाधनों को बढ़ाने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में भी जानकारी दी।

अनुराग ठाकुर

पूर्व केंद्रीय मंत्री व भाजपा सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने प्रदेश सरकार से सिरमौर जिला के माजरा स्थित एस्ट्रोटर्फ मैदान में बिजली का कनेक्शन लगाने और पानी की व्यवस्था का आग्रह किया है। अनुराग सिंह ठाकुर ने आज एक बयान में कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने लगभग 7 करोड़ रूपए की लागत से प्रदेश के लिए इस एस्ट्रोटर्फ का निर्माण किया लेकिन प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने यहां बिजली का कनेक्शन न

लगा कर राज्य के हॉकी खिलाड़ियों के प्रति बेरूखी दिखाई जो निंदनीय है। उन्होंने कहा कि मैदान पर पानी की व्यवस्था न होने पर यहां अभ्यास करने वाले खिलाड़ियों को इस एस्ट्रोटर्फ का फायदा नहीं हो रहा है और पानी की कमी के कारण एसट्रोटर्फ भी खराब हो रहा है।

——————————————